and make a statement in the House and I do feel that this requires an enquiry, a thorough enquiry and this enquiry should be held immediately and the truth has got to be found out and the House has got to be told of the details because in this case, we are quoting only the newspaper. We are not saying anything else. Therefore, I would like the Minister to come forward with a statement here and tell us the truth, as to what the whole thing is.

REFERENCE TO THE REPORTED MOVE TO SHIFT SITE OF CENTRAL WORKSHOP FROM CHANDRAPUR TO HINGANGHAT BY WESTERN COAL FIELD LIMITED

श्री नरेश सो० पुगलिया (महाराष्ट्र) : उपसभाध्यक्ष, महोदय, स्पेशल मेंशन के माध्यम से मैं सरकार का ध्यान एक गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं महाराष्ट्र के जिस चन्द्रपुर जिले से आता हूं जो कि आदिवासी और पिछड़ा हुआ जिला है उस जिले में कोल इण्डिया के माध्यम से जो केन्द्र सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम है किस प्रकार से उनके अधिकारी अपनी मनमानी करते हैं और अपने मंत्री को खुश करने की कोशिश करते हैं और जनता के पैसे की जिस ढंग से बरबादी होती है उस चीज को सदन के सामने रखना चाहता हूं सन 1983–84 में चन्द्रपुर जिला जो कि सारे देश में खनिज सम्पदा और वन सम्पदा के लिए मशहूर माना जाता है जिस जिले का कोयला काश्मीर से ले कर कन्याकुमारी तक जाता है, जहां का लाइम स्टोन और सीमेंट सारे देश में जाता है, जिस जिले में वर्ल्ड का नम्बर-2 का टीक वुड होता है, जिस जिले की कोयले की खानों में लाखों टन हर साल कोयला निकाला जाता है वहां जो इनकी माडर्न टैक्नोलोजी है कोल इंण्डिया की वेस्टर्न कोल फील्ड से कोयला निकालने के लिए उसके अनुसार हमारे जिले में ओपन कास्ट माइनिंग का काम शुरू किया गया है। इसके लिए इन्होंने काफी बड़ी मशीनरी जिसमें एक-एक मशीन की कीमत डेढ़ दो करोड होती है ऐसी मशीनरी लाई है। इसकी रिपेयरके लिए केन्द्रीय सरकार की ओर से एक सेंट्रल वर्कशाप का निर्माण करने का फैसला 1983 में हुआ जिस पर करीब 30 करोड़ रुपये लगने का अनुमान है। वहां के एम० एल० ए० की हैसियत से मैंने वहां के किसानों ने विनती की, उनसे पांच हजार रुपये प्रति एकड़ जमीन कुल पाँच सौ एकड़ वेस्टर्न कोल फील्डस ने उनसे खरीदी है और जिस मुआवजा उनको 25 लाख रुपये दिया गया है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जहां पर कोयला निकालने की मशीनरी है उस रिपेयर के लिये वर्कशाप के निर्माण के बारे में पिछले आठ-दस दिनों से नागपुर के पत्रों में और वहां के रीजनल पेप के माध्यम से जो समाचार छपे हैं उनसे वहां की जनता के बीच असंतोष की भावना आई है क्योंकि हमारे इस वर्कशाप को वहाँ से हटा कर वर्धा जिले की हिंगनघाट तहसील में ले जाया जा रहा है जहां पर कि कोई भी कोयले का डिपोजिट नहीं है। हालांकि वह भी महाराष्ट्र और हमारे देश का एक भाग है। राज्य सभा का सदस्य होने के नाते मैं अपने जिले के लिए या मेरे राज्य के लिए या मेरे देश के किसी भी कोने में बड़ी इंडस्ट्री या वर्कशाप लगती हैं तो उसका स्वागत करना चाहूंगा लेकिन एक बार केन्द्रीय सरकार जिस चीज की घोषणा कर देती है और उसके निर्माण के लिए जमीन भी किसानों से ले लेती है उसके बाद अगर यह प्रोजेक्ट किसी मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में ले जाने के लिए या वहाँ से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर ले जाने के लिए फैसला करते हैं तो यह देश के लिए ठीक नहीं है खासकर के कोल इंडिया के लिए जिसमें करोड़ों रुपये का घाटा सालाना हम लोग भरते हैं, यह जनता की जेब से जाता है। वे लोग अगर गलत निर्णय लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उनका घाटा जो आज सालाना 80–90 करोड़ है वह नीचे होगा। यह दिन-ब-दिन बढ़ेगा।

[उपसभापति महोदय पीठासीन हुये]

उपसभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस वस्टन कोल फील्ड की 5 सौ एकड़ जमीन के ऊपर कारखाना

[श्री नरेश सो० पुगलिया]

बनाने का निर्णय 23 फरवरी, 1986 को घोषित कर चुके हैं, बजट में जिसका प्राविजन आ चुका है, ऊर्जा मंत्रालय ने इस बात का कमिटमेंट किया है कि 1989 तक इस प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जायेगा अगर तीन चार दिन से ये खबरें नागपुर के अखबारों में आई है तो हमारे जिले की जनता में काफी असंतोष फैलना स्वाभाविक है क्योंकि इस वर्कशाप के माध्यम से कुशल, अकुशल 1500 कामगारों को काम मिलने वाला था । जब एक बार केन्द्रीय सरकार घोषणा कर देती है कि हम यह प्रोजेक्ट यहाँ ले जा रहे हैं तो बड़े से बड़ा नेता क्यों न हो लेकिन जनता के हित में सार्वजनिक उपक्रम के हित में ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। इस फैसले पर और खासकर ऊर्जा मंत्री जी ने जो एक गलत जवाब लोकसभा में दिनांक 29-7-86 को दिया है अनस्टार्ड क्वेशचन नं 1574, में, "कि हमने इस वर्धा वैली में जो हमारा प्रोजक्ट होने जा रहा है इसके लिए 23.87 करोड़ का प्राविजन किया है लेकिन साइट का लोकेशन कौन सा होना चाहिए इस बारे मे निर्णय अभी तक नही लिया है" इस पर सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगा। मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि इस प्रकार से लोक सभा में जो गलत उत्तर दिये जाते हैं एक तरफ आप दो साल पहले किसानों की जमीन खरीद लेते हैं उनका पैसा उन्हें दे देते हैं, बजट में एलोकेशन कर देते हैं, इसका मतलब साफ है कि आपने साइट का सिलेक्शन कर लिया है तो इस प्रकार से ऊर्जा मंत्रालय के, या कोल इंडिया के अथवा वेस्टर्न कोल फील्ड के अधिकारी मंत्री महोदय को गलत जानकारी देते हैं जिससे कि वहां की जनता की भावनाएं भड़क चुकी हैं । हमारे जिले से दो लोक सभा के सदस्य हैं और मैं तीसरा राज्य सभा में आ चुका हूं । पुरानी मेरी विधानसभा की कांस्टीट्यूएंसी है, मैं दो बार उस जगह से एम०एल०ए० रह चुका हूं। इस हालत में वहां की जनता ने आन्दोलन करने का फैसला किया है । इस चीज के लिए विरोधी पक्ष और रूलिंग पार्टी के सभी लोग एकत्रित होकर, जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके लिए आवाज उठा रहे हैं । मैं आपसे विनती करता हूं कि आप माननीय ऊर्जा मंत्री साठे जी से कहकर इस सदन को जानकारी दिलाने की कोशिश करें । उन्होंने जो लोकसभा में इस प्रकार से उत्तर दिया है कि साइट का किसी प्रकार से निर्णय नहीं लिया गया है तो मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी डिपार्टमेंट अपने प्रोजेक्ट का निर्माण करता है, बजट में प्राविजन करता है, जमीन किसानों से ले लेता है तो बगैर साइट के सिलेक्शन के इतनी कार्यवाही करता है । इस प्रकार से गलत उत्तर जिन अधिकारियों ने मंत्री महोदय के माध्यम से दिया है उन अधिकारियों की जांच होनी चाहिए । वे भ्रष्ट अधिकारी हैं अपने मंत्रालय के मंत्री को खुश करना चाहते हैं इसलिए, उनके निर्वाचन क्षेत्र में वर्कशाप बनाएंगे जहां कोल माइंस नहीं हैं, एक टन कोयला जहां से नहीं निकल सकता है जबकि हमारे यहां 22 कोल माइंस हैं और 20 नयी खुलने जा रही हैं, थर्मल पावर स्टेशन हैं । ऐसी हालत में इसको गम्भीरता से लेकर विचार करने के लिए मैं हाउस के माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा ।

SHRI JAGESH DESAI (Maharashtra): Mr. Deputy Chairman, Sir, I would like to add something on this. Chandrapur is the most backward district in Maharashtra. And the policy the Government is to encourage industries in backward districts. As such, the site should not be changed. It should be kept at Chandrapur.

REFERENCE TO THE REPORTED EXPORT OF CHEAP QUALITY OF BASMATI RICE BY TWO PRIVATE FIRMS TO USSR

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) माननीय डिप्टी चेयरमन महोदय, रूस: सरकार ने भारत सरकार से उत्तम किस्म के बासमत. चावल मंगाने के दो आदेश प्लेस किये थे । दीक्षा होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड और रामा एसोसियेट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक दो कम्पनियों ने 46 हजार टन बासमती चावल रूस को भेजा